जबतक आपके पास संयम और धैर्य नहीं है तबतक आपके सपने राख में मिलते रहेंगे।
– अज्ञात

देश का पहला सीडीएस

रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया। सीडीएस का दायित्व थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा।

आरती सिंह

एक नए साल और दशक के पहले दिन मन में पहला ख्याल यह आता है कि हम क्या–क्या लेकर आगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति ही नहीं, देश के संदर्भ में भी यह प्रश्न उठता है। बीता दशक भारी बदलावों के लिए याद किया जाएगा, खासकर प्रशासनिक कामकाज के स्तर पर। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के शुरुआती छह महीनों में कुछ नई संस्थाएं बनाईं तो कुछ का रूप बदल दिया। इसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि वह कामकाज की जड़ता को तोड़कर एक नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहती है। वह चाहती है कि नौकरशाही की जटिलता समाप्त हो, त्वरित फैसले हों और जनता को इसका लाभ मिले।

इस दृष्टि से सरकार ने योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग गठित किया। कहा गया कि योजना आयोग ऊपर से योजनाएं थोपता रहा है जबकि नीति आयोग ग्राम स्तर से योजनाएं बनाकर ऊपर तक पहुंचाएगा। आरबीआई के कामकाज में तब्दीली के लिए सरकार ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाना है। नौकरशाही में सुधार के मकसद से सरकार ने विभिन्न विषयों पर सचिवों के आठ समूहों का गठन किया और फिर सिविल सेवा में लैटरल एंट्री का प्रावधान किया जिसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों में सीधे संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया। सीडीएस का दायित्व थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। रेलवे की आठ विभिन्न सेवाओं को मिलाकर एक श्इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसश नामक एक नई सेवा का गठन किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड का ढांचा भी बदलेगा और इसमें कई स्वतंत्र अनुभवी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक मशीनरी का आदर्श यही है कि वह अपने चरित्र में ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रित, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह हो लेकिन मोदी सरकार के ढांचागत बदलाव पहली नजर में केंद्रीकरण की ओर झुके जान पड़ते हैं। स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं का भी कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्टों में जमीनी समझ की कमी है। उसके पास योजना आयोग जैसे अधिकार भी नहीं हैं। ऐसे में उसके होने का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिजर्व बैंक में बदलाव से गवर्नर की स्वायत्तता बाधित होने की बात कही जा रही है। आरबीआई के फैसले सरकार की चिंताओं से संचालित जान पड़ते हैं। नौकरशाही में लैटरल एंट्री या रेलवे सर्विस में बदलाव को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि इससे नौकरशाही में चाटुकारिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सीडीएस को लेकर भी शंकाएं बहुत हैं लेकिन इसके कामकाज से जुड़े ब्यौरे अभी आने बाकी हैं। इन सारे बदलावों की असल परीक्षा 2020 के दशक में ही होनी है।

वही सत, वही आत्मा

धर्म-दर्शन

सुंदरचंद ठाकुर। अन्य उपनिषदों की तरह, छान्दोग्य उपनिषद में भी आत्मा, सत, ब्रह्म, परब्रह्म आदि की विवेचना हुई है । इसी संदर्भ में आरूणि तथा श्वेतकेतु का वार्तालाप है !

ऋषि आरूणि का पुघ्त्र श्वेतकेतु गुरूकुल में विद्याध्ययन कर जब घर वापस आया, तब पिता को अनुभूति हुई कि पुत्र में कुछ घमण्ड आ गया है। पिता ने कहा – ''बेटे, तुम समझते हो कि तुम सब जान गए हो, पर यह तो बताओ कि क्या तुम ने वह विद्या पढ़ी है, जिसे पढ़कर सब कुछ पा लिया जाता है ? श्वेतकेतु ने कहा –''वह तो मैं नहीं जानता, आप मुझे बतलाइए।'' इसी मिट्टी से हाथी, घोड़ा, तोता, कबूतर, राजा, रानी, बिल्ली आदि के खिलौने बन सकते हैं। सब के नाम अलग, सब के चेहरे अलग। ये मिट्टी के पात्र और पदार्थ पानी में डालते ही गल जाते हैं।

संपादकीय

पुलिस और सशस्त्र बल

यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं कि दुनिया भर में मौजूद 1 अरब 1 करोड़ छोटे हथियारों का 84.6 प्रतिशत सिविलियंस यानी आम नागरिकों के पास है। आम नागरिक, यानी पुलिस और सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी सब। दूसरे शब्दों में कहें तो निजी सुरक्षा कंपनियों, गैर सरकारी सशस्त्र संगठनों और गिरोहों को भी इसमें शामिल किया गया है। हथियारों पर नजर रखने वाले जिनेवा स्थित संगठन 'स्मॉल आर्म्स सर्वे' की पिछले साल जून में प्रकाशित रिपोर्ट 'एस्टिमेटिंग ग्लोबल सिविलियन हेल्ड फायरआर्म्स नंबर्स' के अनुसार 2017 में कुल हथियारों का 13.2 प्रतिशत (13.30 करोड़) ही राज्य के नियंत्रण वाली सेना और 2.2 प्रतिशत (2.30 करोड़) विभिन्न सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास था।

रिवॉल्वर, सेल्फ लोडिंग पिस्टल, राइफल, कार्बाइन और असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीनगन तक को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। इस तरह के हथियारों में पिछले दस सालों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन्हें रखने वाले आम नागरिक मुख्यतरू अमेरिका, भारत, चीन और पाकिस्तान के हैं। अमेरिका में दुनिया की सिर्फ 4 प्रतिशत आबादी रहती है मगर वहां के नागरिकों के पास दुनिया के 40 प्रतिशत छोटे हथियार हैं। वहां लोगों के पास कुल 39 करोड़ 33 लाख, यानी औसतन 10 नागरिकों पर 12 हथियार हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 50 साल से ऊपर के एक तिहाई अमेरिकियों के पास जबकि 18 से 29 वर्ष आयुवर्ग के 28 प्रतिशत युवाओं के पास बंदूकें हैं। इस मामले में अमेरिका के बाद भारत (7.11 करोड़), चीन (करीब 5 करोड़), पाकिस्तान (4.39 करोड़) और रूस (1.76 करोड़) का नंबर आता है। न्यूजीलैंड में आम लोगों के पास केवल 12 लाख हथियार हैं।

इस साल के अंत में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर बीजेपी को लग रहा है कि मुद्दा उसकी पिच पर है जिससे उसे सियासी प्रीमियम मिलेगा।

बीजेपी और विपक्ष लिए चुनौती

नरेंद्र नाथ

2020 में सबसे बड़ी सियासी चुनौती मुद्दों को अपने पिच पर रखने की है। बीजेपी और विपक्ष, इनमें से जो भी अपने मुद्दों को सियायत के केंद्र में रखने में सफल होगा, वह फायदा उठाएगा। वैसे वर्ष 2014 से बीजेपी लगातार इस मोर्चे पर बीस पड़ी है। इस साल के अंत में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर बीजेपी को लग रहा है कि मुद्दा उसकी पिच पर है जिससे उसे सियासी प्रीमियम मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मिश्रण से बने मुद्दे को बीजेपी ने ऐसा कवच बनाया है जिसे भेदने का नुस्खा विपक्ष अब तक नहीं तलाश पाया है। बीजेपी ने इन्हीं से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर पूरी राजनीति को बदल दिया है। अब विपक्ष पूरी ताकत से अपने मुद्दों को अपनी पिच पर लाने की कोशिश में है। आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच विपक्ष रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे को मुख्यधारा में लाना चाह रहा है। आर्थिक मोर्चे पर 2020 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2019 इस मामले में मोदी सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं रहा लेकिन अब जबकि अगले साल ज्यादा चुनाव नहीं हैं तो पूरा फोकस इन मुद्दों पर आ सकता है।

मेक मोमेंट से ब्रेक मोमेंटः अभी तक के जो संकेत हैं, उस हिसाब से मुद्दों के मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार रह सकती हैं। मोदी सरकार इनसे कैसे उबरती है, उसका असर राजनीति पर निश्चित तौर से पड़ेगा। रोजगार से लेकर जीडीपी ग्रोथ तक के आंकड़े उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। राजनीति में धारणा और मुद्दे बेहद अहम माने जाते हैं। जो इनका अजेंडा सेट करता है, वह स्वाभाविक रूप से लाभ में रहता है। अगर बीजेपी इन चुनौतियों के बीच अगले साल भी अपने हिसाब से अजेंडा सेट करने में सफल रहती है तो विपक्ष के लिए आने वाला वक्त और कठिन हो सकता है। जाहिर है कि इसके लिए हर स्तर पर बहुत ही आक्रामक जंग देखने को मिल सकती है। हाल के समय में ऐसा देखा गया है कि राजनीति 24 घंटे की हो गई है जहां कोई भी एक पल किसी के लिए मेक मोमेंट से ब्रेक मोमेंट बन जाता है। ऐसे पल को कौन सा पक्ष किस तरह से अपनी ओर मोड़ने में सफल या विफल रहता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।

बिसात चुनावी मोर्चे कीः 2020 में मात्र दो राज्यों में चुनाव होने हैं। साल के शुरू में दिल्ली तो साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। जाहिर है, इन्हीं दो राज्यों के परिणामों के आधार पर बहुत कुछ तय होगा। चूंकि दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की ताकत की भी परख होगी तो उससे भी विपक्षी राजनीति की दिशा तय होगी। राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए भी अहम होंगे। वह भी तब, जब आम चुनाव में बड़ी जीत के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बाकी का साल कोई खास उत्साहवर्धक नहीं रहा। दो राज्यों में पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। यह साल अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए भी अहम होने वाला है। इस साल का अंत होते–होते दो अन्य राज्यों में सियासी दंगल की बुनियाद पड़ चुकी होगी। एक पश्चिम बंगाल और दूसरा असम। इन दोनों राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे।

सूडोकु नवताल- 5217

★★★★☆ कठिन

	8	5						
3								
			6			7	4	
6			2		4			
1								8
			7		5			3
	4	7			1			
								6
						5	2	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5216 का हल

4	3	9	2	6	8	5	1	7
8	1	6	7	4	5	9	2	3
7	5	2	3	9	1	6	4	8
1	7	5	4	2	6	8	3	9
6	4	3	8	5	9	2	7	1
2	9	8	1	7	3	4	5	6
5	2	1	6	8	7	3	9	4
9	8	7	5	3	4	1	6	2
3	6	4	9	1	2	7	8	5

अपना ब्लॉग: जहर है कि जाता नहीं

चंद्रभूषण। बड़े लेखकों की रवां लिखाई को हल्के में लेना हमारे समाज के लिए आम बात है। प्रेमचंद की कहानी 'दो बैलों की कथा' नीचे की कक्षाओं में लगी हुई मिलती है। हल–बैल बच्चों के जीवन से जैसे–जैसे बाहर जा रहे हैं, वैसे–वैसे उनके लिए इसको समझना भी मुश्किल होता जा रहा है लेकिन असल समस्या बड़ों के साथ है जो इसे पशुप्रेम के सरल नैतिक उपदेश के रूप में खुद भी ग्रहण करते हैं और यही घुट्टी बच्चों को भी पिलाते हैं। इस कहानी का उर्दू रूप 'दो बैल' है और रेख्ता की साइट पर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। 'दो बैलों की कथा' और 'दो बैल' को अगल–बगल रखकर पढ़ें तो दोनों में कुछ मोटे फर्क नजर आते हैं। एक तो यह कि हिंदी वाली कहानी दो–तीन पैरा लंबी है। उसमें शुरू में ही अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा को लेकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उर्दू में नदारद है।

ज्यादा बड़ा फर्क यह कि उर्दू में हीरा और मोती तकरीबन एक–से बैल हैं जबकि हिंदी में अति सहनशील हीरा के मुकाबले मोती का एक गुस्सैल, प्रो–ऐक्टिव कैरक्टर है। इसमें एक–डेढ़ पैरा उन घटनाओं पर भी खर्च किए गए हैं जिनसे मोती का किरदार निखरता है।